

# Daily Current Affairs

Date : 06 February, 2026



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, 2024 (EPI) में राजस्थान का प्रदर्शन
2.	45वीं छात्रकला प्रदर्शनी के पुरस्कारों की घोषणा
3.	डॉ. ओपी माचरा: दूसरा शूटिंगबॉल वर्ल्ड कप
4.	हाड़ौती वन मेला
5.	ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट
6.	राजस्थान में सेम की समस्या
7.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. सतत विकास में जीवन विज्ञान और वानिकी की अहम भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस
8.	उर्मिया झील
9.	स्थानीय निकाय: 16वाँ वित्त आयोग
10.	भारत में बुजुर्गों की देखभाल: केंद्रीय बजट 2026-27
11.	FORGE पहल
12.	अभ्यास खंजर
13.	कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS): केंद्रीय बजट 2026-27

--:1:--



Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213  
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



## राजस्थान परिदृश्य



### एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, 2024 (EPI) में राजस्थान का प्रदर्शन



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, 2024 (EPI) में राजस्थान 4 स्थान और फिसल कर 13वें से 17वें स्थान पर पहुँच गया है।

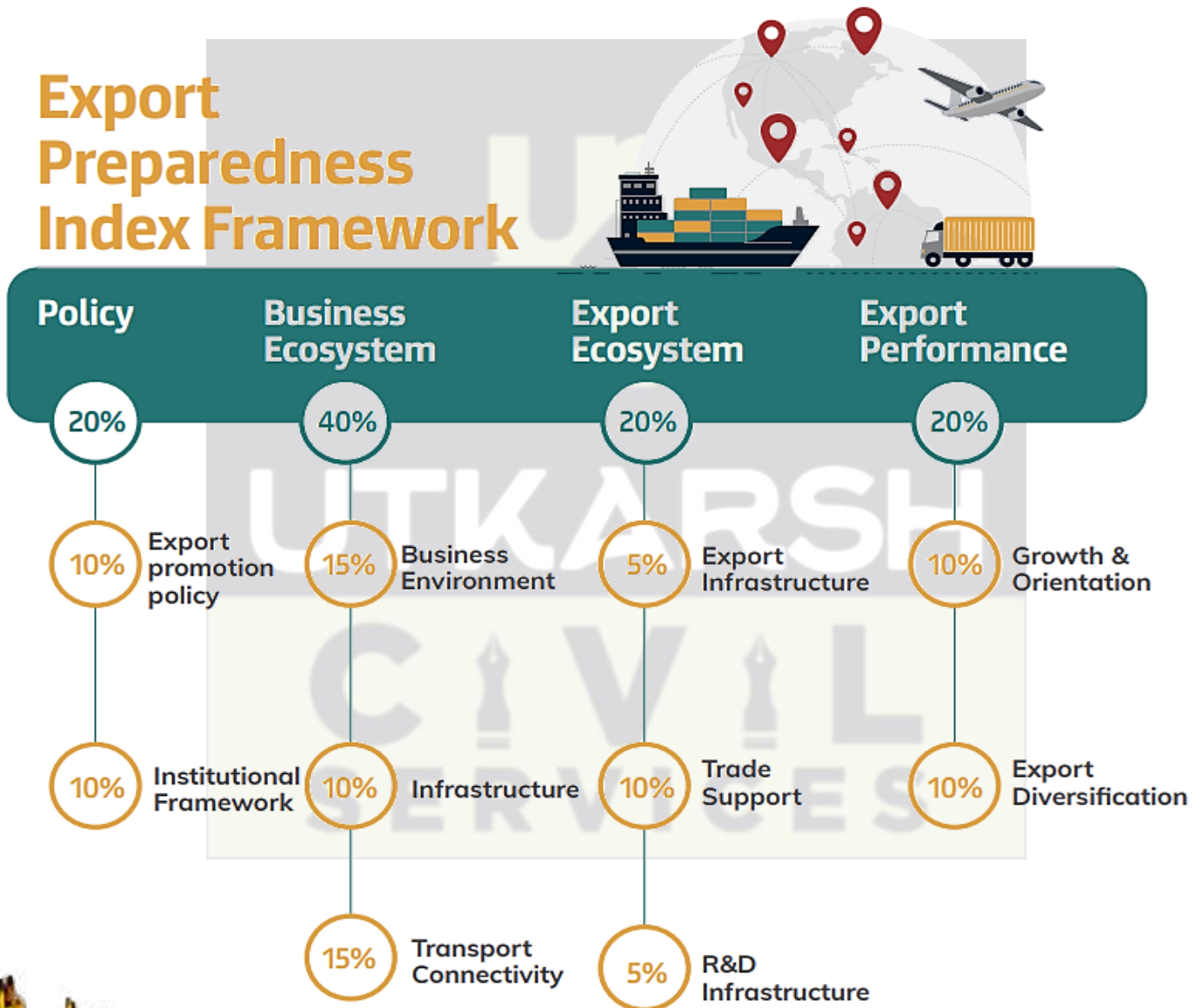


#### मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता का आकलन करता है तथा वर्ष 2030 तक भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य और विकसित भारत @2047 के विज़न को प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- जरिकर्ता:** नीति आयोग
- शुरुआत:** पहली बार वर्ष 2020 में शुरू किया गया, यह सूचकांक प्रमाण-आधारित ढाँचे के माध्यम से राज्य और ज़िला स्तर पर निर्यात तैयारियों का आकलन करता है।

- **EPI 2024 का रूपरेखा और विवरण:** यह 4 स्तंभों, 13 उप-स्तंभों और 70 संकेतकों के आधार पर संरचित है।
- **चार मुख्य स्तंभ हैं:** निर्यात अवसंरचना, बिज़नेस इकोसिस्टम, नीति व शासन और निर्यात प्रदर्शन।

## Export Preparedness Index Framework



- **वेटेज:** इन चारों में बिज़नेस इकोसिस्टम को सबसे अधिक 40 प्रतिशत वेटेज दिया गया है, जबकि शेष तीन स्तंभों को 20-20 प्रतिशत का भार प्रदान किया गया है। यह लागत दक्षता, MSMEs, वित्त तक पहुँच और नवाचार के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है, जो निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मज़बूत करने में सहायक हैं।

- **श्रेणियाँ:** तुलनात्मक आकलन के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। साथ ही उन्हें लीडर्स (उच्च निर्यात तत्परता), चैलेंजर्स (मध्यम तत्परता, सुधार की संभावना) एवं आस्पायरर्स (प्रारंभिक चरण की निर्यात पारिस्थितिकी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे पीयर लर्निंग, सहकारी संघवाद व लक्षित सुधारों को बढ़ावा मिलता है।
- **सूचकांक का महत्त्व:** बजट में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा वैश्विक अस्थिरता के बीच राज्यों को दीर्घकालिक विकास, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और ग्लोबल वैल्यू चेन में रणनीतिक तालमेल के लिए निर्यात की तत्परता बढ़ाने की आवश्यकता होंगी।
- यह निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के एकीकरण में राज्यों तथा ज़िलों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है तथा अवसंरचना विकास, प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता एवं क्लस्टर-आधारित रणनीतियों पर विशेष बल देता है।
- यह सूचकांक संघवाद और आर्थिक प्रदर्शन के बीच संबंध को दर्शाता है तथा ज़िला-आधारित निर्यात वृद्धि को प्रमुखता देता है, जिससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) और व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को समर्थन मिलता है।
- **राजस्थान का प्रदर्शन (17 वाँ स्थान):** रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान निर्यात की तैयारी में पीछे जरूर हुआ, लेकिन औद्योगिक वातावरण बनाने में बेहतर स्थिति में रहा, जबकि सबसे बड़े मैनुफैक्चरिंग सेक्टर MSME का इकोसिस्टम बनाने में कमजोर स्थिति में रहे।

# Daily Current Affairs

Date : 06 February, 2026



राजस्थान की स्थितियों को नीति आयोग ने 4 पिलर्स और उनके सब पिलर्स को पैमाना बनाया है:

EC में 1.2 और इन्फ्रा सुविधा में 1.5 का ही स्कोर

पिलर्स	सब पिलर्स	कुल स्कोर	प्राप्त स्कोर
एक्सपोर्ट	बिजली व पानी	10	4.6
इन्फ्रास्ट्रक्चर	लॉजिस्टिक, स्टोरेज कैपेसिटी	10	2
बिजनेस	इकोनॉमी आउटपुट मैनुफैक्चरिंग	10	4.1
इकोसिस्टम	बिजली-पानी में कॉस्ट कम्पेरिजन	5	3.5
	ह्यूमन कैपिटल	5	2.26
	वित्त व क्रेडिट एसेसिबिलिटी	5	2
	MSME इकोसिस्टम	10	2.1
पॉलिसी-गवर्नेंस	औद्योगिक व नवाचार वातावरण	5	4.1
	पॉलिसी सपोर्ट व एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन	15	9.4
	EC व अन्य	5	1.2
एक्सपोर्ट	एक्सपोर्ट ट्रेड्स	5	3.8
परफॉर्मेंस	इन्फ्रा सुविधा	5	1.5
	बाजार व कमोडिटीज	10	6.4

- **MSME इकोसिस्टम का प्रदर्शन:** प्रदेश का इकोसिस्टम, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार खराब स्थिति में है। यानी कुल 10 में से रिपोर्ट में इसे सिर्फ 2.1 अंक दिए गए हैं। जबकि पर्यावरण क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने, सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन और डिजिटल मैच्योरिटी में भी 5 राज्य की खराब स्थिति के कारण निर्यात तैयारी पर असर पड़ा है। लॉजिस्टिक स्टेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार करने में भी राजस्थान काफी पीछे हैं।

--5--

# Daily Current Affairs

Date : 06 February, 2026



- **औद्योगिक वातावरण और प्रदर्शन:** राजस्थान भले ही राज्य निर्यात तैयारी में कमजोर हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक वातावरण बनाने में बेहतर स्थिति (5 में से 4.1 स्कोर) में हैं। साथ ही नवाचार में भी आगे हैं। इसी तरह सरकार की पॉलिसी सपोर्ट भी बेहतर रहा है।

**अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:**

**EPI, 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:**

बड़े राज्य	छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
महाराष्ट्र	उत्तराखंड
तमिलनाडु	जम्मू और कश्मीर
गुजरात	नगालैंड
उत्तरप्रदेश	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
आंध्र प्रदेश	गोवा

--:6:--

## 45वीं छात्रकला प्रदर्शनी के पुरस्कारों की घोषणा

### चर्चा में क्यों?

- 5 फरवरी, 2026 को राजस्थान ललित कला अकादमी की 45वीं छात्रकला प्रदर्शनी के निर्णायक मण्डल ने राज्य के 10 छात्र-छात्राओं की कलाकृतियों को पुरस्कार योग्य घोषित किया है।



### मुख्य बिन्दु:

- कलाकृतियाँ:** इस प्रदर्शनी में राज्य भर से 208 छात्र-छात्राओं की 536 कलाकृतियाँ प्राप्त हुई थीं, जिसमें निर्णायक मण्डल ने प्रदर्शनी के लिये 110 छात्र-छात्राओं की 145 कलाकृतियों का चयन किया।
- पुरस्कृत कलाकृतियाँ:** अरुण कुमार कुमावत, नागौर (एसेडिंग ग्रेण्डूयर), हर्षा सोनी, ब्यावर (द वाल्स आफ प्रोग्रेस), विजय, जोधपुर (जोधपुरी जारोखा), अनन्या सैनी, अजमेर (चित्तौड़गढ़-1), प्राची शर्मा, जयपुर (मेमोरी लेन), याशिका जांगिड़, (वाईव आफ राजस्थान), सौरभ यादव, अलवर (जीवन संघर्ष 1), कृष्णकांत टंगुरिया, (वाट अबाउट अस), श्वेता चौहान, जयपुर (अनटाईटिल्ड-1) धर्मेन्द्र पंडित (कंधों पर समाज)।
- पुरस्कार राशि:** प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर पुरस्कृत 10 छात्र-छात्राओं को दस-दस हजार रुपये के नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किये जायेंगे।

## डॉ. ओपी माचरा: दूसरा शूटिंगबॉल वर्ल्ड कप

### चर्चा में क्यों?

- 1 से 3 फरवरी, 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित दूसरे शूटिंगबॉल वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में मेडल जीते हैं।
- राजस्थान शूटिंगबॉल के महासचिव डॉ. ओपी माचरा ने पुरुष टीम के कोच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



### मुख्य बिन्दु:

<b>महिला वर्ग:</b> स्वर्ण पदक (नेतृत्व: प्राजक्ता अवले)	<b>पुरुष वर्ग:</b> रजत पदक (नेतृत्व: सुरेश बिश्रोई)
भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता।	भारतीय पुरुष टीम, कनाडा से हराकर रजत पदक जीता।
<b>रजत पदक:</b> नेपाल <b>कांस्य पदक:</b> म्यांमार	<b>स्वर्ण पदक:</b> कनाडा <b>कांस्य पदक:</b> न्यूजीलैंड

- टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी:** कनाडा टीम के कप्तान रजपाल सिंह बागड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
- मोना जाट:** राजस्थान की मोना जाट भी महिला टीम की सदस्य थीं।
- Note:** डॉ. माचरा ने पहले भी नेपाल में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने में सहायता की थी।

## हाड़ौती वन मेला



# हाड़ौती वन मेला

अयोजक: राजस्थान वन विभाग, कोटा संभाग

स्थान: आर्टगैलेरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प बाजार कोटा दिनांक: 7 - 8 Feb 2026

### मुख्य आकर्षण

- वनोपज एवं हर्बल प्रोडक्ट्स की मनमोहक प्रदर्शनी एवं क्रय - विक्रय ।
- Territorial Kota, Bundi, Baran, Jhalawar, MHTR, RVTR, Kota Wildlife की स्टॉल एवं प्रदर्शनी ।
- पक्षी एवं वन्यजीव विशेषज्ञों की प्रस्तुति ।
- पक्षियों पर फोटोग्राफी एवं स्टेम्प प्रदर्शनी ।
- वन्यजीव एवं मानव सह अस्तित्व पर टॉक शो और नुक्कड़ नाटक ।
- बर्ड वार्चिंग ।

प्रकृति के इस अनूठे उत्सव 'वन मेला' में आपका हार्दिक स्वागत है; आइए, प्रकृति के करीब आएं, पारंपरिक उत्पादों का आनंद लें और इस खास आयोजन को सफल बनाएं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं।



WILDLIFEDIVISIONKOTA

dcfwl232@gmail.com

--:9:--



## मुख्य बिन्दु:

- आयोजन तिथि: 7-8 फरवरी, 2026 तक।
- आयोजन स्थल: आर्टगैलेरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प बाजार, कोटा
- अयोजक: राजस्थान वन विभाग और कोटा संभाग द्वारा।

## मुख्य गतिविधियाँ:

- वनोपज एवं हर्बल प्रोडक्ट्स की मनमोहक प्रदर्शनी एवं क्रय-विक्रय।
- क्षेत्रीय कोटा, बूँदी, बारां और झालावाड़, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व/MHTR (मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य), रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व/RVTR, कोटा वन्यजीव की स्टॉल एवं प्रदर्शनी।
- पक्षी एवं वन्यजीव विशेषज्ञों की प्रस्तुति।
- पक्षियों पर फोटोग्राफी एवं स्टेम्प प्रदर्शनी।
- वन्यजीव एवं मानव सह अस्तित्व पर टॉक शो और नुक्कड़ नाटक।
- बर्ड वाचिंग।

## अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- हाड़ौती प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति: प्रदेश में मूलरूप से उष्ण-शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। यहाँ निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं -
  - (1) धोकड़ा वन
  - (2) मिश्रित वन
  - (3) खेर के वन
  - (4) घास के मैदान एवं झाड़ियाँ
- उपर्युक्त वर्गीकरण राज्य वन-विभाग द्वारा स्थानीय आधार पर किया गया है-

- (1) **धोकड़ा वन:** वनों का विस्तार हाड़ौती के विस्तृत क्षेत्रों में हैं। ये पर्वत श्रेणियों की ढालों पर एवं अन्य असमतल भूमि में पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि मंद होती है तथा पेड़ों की ऊँचाई 7.5 मीटर तक होती है। ये बूँदी की पहाड़ियों, मुकन्दवारा की श्रेणियों एवं शाहबाद क्षेत्र में अधिक विस्तृत हैं।
- इनमें धोकड़े के पेड़ के अतिरिक्त तेंदू, खेर, बेल, गुर्जन, सिरिस आदि भी मिलते हैं। व्यापारिक दृष्टि से तेंदू की पत्तियों का सर्वाधिक महत्त्व है, क्योंकि ये बीड़ी बनाने के काम आती हैं।
- (2) **मिश्रित वन:** पर्वत-श्रेणियों की तलहटियों में और नदियों के किनारे मिलते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष जैसे - खेर, बेल, तेंदू, गुर्जर, खेजड़ा, आँवला, बहेड़ा, जामुन, खिरनी, सेलार, मेमली आदि मिलते हैं। जहाँ नमी की दशा उपयुक्त होती है, वहाँ बाँस भी मिलता है। चन्दन के वृक्ष डग-पिड़ावा तहसील झालावाड़ में व कनवास कोटा में मिलते हैं।
- (3) **खेर के वन:** खेर के वन भी मिश्रित अवस्था में पर्वतीय ढालों एवं मैदानी भागों में मिलते हैं। ये वन पिड़ावा, बकानी (झालावाड़) तथा सांगोद, बारां, शाहबाद (कोटा) एवं नैनवा, हिण्डोली (बूँदी) में विशेषकर मिलते हैं।
- घास के बीड़ (सघन क्षेत्र) हाड़ौती में अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं, जहाँ प्राकृतिक रूप से घास एवं झाड़ियाँ उग आती हैं।
  - उपर्युक्त के अतिरिक्त टीक, बाँस, बबूल के वन भी यहाँ हैं। यहाँ के वनों से इमारती लकड़ी, बाँस, गोंद, लाख, तेन्दू का पत्ता (बीड़ी बनाने हेतु) प्राप्त की जाती। साथ ही भारी मात्रा में ईंधन हेतु लकड़ी काटी जाती है। अनियमित कटाई के कारण विगत दस वर्षों में वनों का अत्यधिक ह्रास हुआ है। जहाँ सघन वनों का विस्तार था, वे श्रेणियाँ अब नग्न नजर आने लगी हैं।

## ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट

### चर्चा में क्यों?

- फरवरी, 2026 में जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर-15 बॉयज डबल्स में राजस्थान के वयम लांबा और श्रेयांश चौधरी ने चैम्पियनशिप जीती हैं।



### मुख्य बिन्दु:

#### अंडर-15 बॉयज डबल्स:

- फाइनल:** वयम-श्रेयांश ने फाइनल में उत्तराखंड के आदित्य सिंह नेगी व झारखंड के सम्वित रमेश 22-20, 26-28, 21-18 से हरा खिताबी जीत हासिल की।
- मैच की अवधि:** इस जोड़ी ने 72 मिनट चले फाइनल मैच में जीत हासिल की, जो टूर्नामेंट का सबसे लम्बा मुकाबला रहा।

--:12:--

## अंडर-15 मिक्स्ट डबल्स:

- **फाइनल:** अंडर-15 मिक्स्ट डबल्स में राजस्थान के मनन शर्मा व पंजाब की इनायत गुलाटी को फाइनल में तमिलनाडु की सेकंड सीड जेसिका निधिघंटी व टी.एम.एफ. की जोड़ी ने 14-21, 15-21 से हराया। जेसिका निधिघंटी ने भी दोहरी सफलता हासिल की।
- **एकल चैम्पियन:** अंडर-15 बॉयज एकल में असम के अनिकेश दत्ता जबकि अंडर-17 में तमिलनाडु के नीरज नायर चैम्पियन बने।
- **तेलंगाना की जुड़वां बहनों को खिताब:** अंडर-17 गर्ल्स डबल्स में तेलंगाना की जुड़वां बहनें आराध्या गारी व अवनी गारी की जोड़ी चैम्पियन बनी। गारी बहनों ने तमिलनाडु की अनुष्का जेनिफर और दिशीथा गोपीनाथ सिंह को हराया।
- **अंडर-15 गर्ल्स एकल:** गर्ल्स एकल में आर्यमा और हिमांशी चैम्पियन अंडर-15 गर्ल्स एकल में प. बंगाल की आर्यमा चक्रवर्ती और अंडर-17 में हिमांशी चंदाराम ने खिताब जीता।
- **फाइनल:** फाइनल में 5वीं सीड आर्यमा ने टॉप सीड तेलंगाना की हिमांशी चंदाराम को हराकर खिताब जीता। हिमांशी ने अंडर-17 फाइनल में महाराष्ट्र की घटा सूर्यवंशी को हराया।
- **अंडर-15 गर्ल्स डबल्स:** अंडर-15 गर्ल्स डबल्स में अनुश्री जी.एस. व जेसिका निधिघंटी चैम्पियन बनीं।

## राजस्थान में सेम की समस्या

### चर्चा में क्यों?

- भू जल मंत्री कन्हैया लाल ने विधानसभा में श्री गंगानगर जिले के रायसिंहनगर, सूरतगढ़ एवं करणपुर भू जल लेवल शून्य होने (सेम) की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
- कृषि विभाग के आँकड़ों के अनुसार तीन विधानसभा क्षेत्र रायसिंहनगर, सूरतगढ़ एवं करणपुर सेम (भू जल लेवल शून्य होने) से प्रभावित हैं।





## मुख्य बिन्दु:

- **सेम की समस्या:** नहरी सिंचित क्षेत्रों में भूजल स्तर के ऊपर आने से भूमि का दलदली और अनुपजाऊ (बंजर) हो जाना है।
- **राजस्थान के प्रभावित क्षेत्र:** हनुमानगढ़ (बड़ोपल, भगवानदास, देईदास), श्रीगंगानगर और बीकानेर।

## सेम की समस्या के कारण:

- इंदिरा गाँधी नहर (IGNP) क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई।
- मिट्टी के नीचे जिप्सम या चूना पत्थर की अभेद्य परत का होना, जिससे पानी नीचे नहीं रिसता।
- जल निकासी का उचित प्रबंध न होना।
- श्रीगंगानगर में सेम की समस्या का मुख्य कारण: नहरों से पानी के रिसाव और बारिश का पानी इकट्ठा होना।
- पंजाब के मुक्तसर जिले में लगातार बाढ़ से पानी का जलस्तर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। इससे श्रीगंगानगर के कुछ क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही इस वर्ष सतलज, रावी, व्यास नदियों में रिकॉर्ड बारिश के कारण भी करणपुर में जल भराव और बाढ़ की स्थिति बनी है।
- **प्रभावित भूमि:** श्रीगंगानगर जिले में 06 विधानसभा क्षेत्र में से रायसिंहनगर के 23 गाँवों का 10584.98 बीघा क्षेत्र सैम से प्रभावित है। सूरतगढ़ के 15 गाँवों का 2450.72 बीघा क्षेत्र सैम से प्रभावित है। इसी प्रकार करणपुर के 17 गाँवों का 6432 बीघा क्षेत्र सैम से प्रभावित है।

## प्रयास:

1. **जिला स्तरीय समिति:** सेम से भवनों और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान और सर्वेक्षण के लिए जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा विभिन्न विभागों की सम्मिलित जाँच समिति का गठन किया गया है।

- जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा पंजाब के सेम प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर वहाँ इसके प्रबंधन के लिए किये जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाएगा तथा विभाग द्वारा लगातार भूजल के स्तर की भी मॉनिटरिंग की जा रही है।
- 2. **ड्रेन निर्माण:** राज्य सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान के लिए पदमपुरा एवं संगीता क्षेत्र में ड्रेन निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
- 3. **इंदिरा गाँधी नहर की रीलाइनिंग:** श्रीगंगानगर जिले में भू जल विभाग द्वारा किए गए प्री-मानसून एवं पोस्ट मानसून सर्वेक्षण के अन्तर्गत वर्ष 2020 से 2025 तक का ब्लॉकवार औसत भूजल स्तर का विवरण सदन के पटल पर रखा। इसके अनुसार जल संसाधन विभाग (उत्तर) द्वारा सेम की समस्या के निवारण हेतु RWSRPD योजना के अन्तर्गत इंदिरा गाँधी नहर तथा अनूपगढ़ शाखा, संगीता वितरिका से रिसाव को रोकने के लिए नहरों की रीलाइनिंग का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। जिससे लगभग 10 हजार 345 बीघा सैम मुक्त हुआ है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।
- **नोट:** वर्तमान सेम की समस्या के निवारण हेतु ग्राम पंचायत पदमपुरा, संगीता, चक4 एस.डी. व 2 एस.डी. के सैम से खराबा होने से बचाने के लिए RWSRPD योजना के अन्तर्गत सैम निवारण हेतु 40.64 करोड़ की राशि के दो कार्य प्रगतिरत हैं। जिनमें पदमपुरा एवं संगीता क्षेत्र में भू-जल स्तर को कम करने के लिए ड्रेन (नाली/निकासी) का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से एकत्रित पानी को पम्प हाउस द्वारा अनूपगढ़ शाखा नहर में डाला जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनों कार्य जून, 2026 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

## सेम की समस्या का समाधान और प्रबंधन:

1. **वृक्षारोपण:** दलदल वाले क्षेत्रों में यूकेलिप्टस (सफेदा) के पेड़ लगाना, जो पानी को सोखते हैं।
2. **जल निकासी:** बड़ोपल में पंप लगाकर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना (घग्गर डायवर्सन चैनल)।
3. **परियोजनाएँ:** नीदरलैंड के सहयोग से 'इंडो-डच जल निकासी परियोजना'।

# Daily Current Affairs

Date : 06 February, 2026



4. कनाडा सहयोग: चंबल क्षेत्र में सेम समस्या के लिए कनाडा के सहयोग से 'राजाद परियोजना' (RAJAD) चलाई जा रही है।

**अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:**

**राजस्थान के पारिस्थितिकीय प्रदेश:**

वृहद् प्रदेश	मध्य श्रेणी प्रदेश
1. मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र	(i) शुष्क प्रदेश (ii) नहरी क्षेत्र (iii) लूनी बेसिन
2. अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र	(i) उत्तरी अरावली प्रदेश (ii) मध्य अरावली प्रदेश (iii) दक्षिणी अरावली प्रदेश
3. पूर्वी-मैदानी पारिस्थितिक तंत्र	(i) बनास बेसिन (ii) माही बेसिन (iii) बाणगंगा बेसिन (iv) साबी बेसिन (v) गम्भीर बेसिन (vi) बेड़च बेसिन
4. हाड़ौती पठार पारिस्थितिक तंत्र	(i) चम्बल बेसिन (ii) बीहड़ क्षेत्र

**मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएँ:**

1. मरुस्थलीकरण।
2. अनियन्त्रित पशु चारण, वनस्पति विनाश, चरागाहों का विनाश, खनिज खनन, मृदा क्षरण व अकाल।
3. लवणता एवं क्षारीयता।
4. सेम की समस्या (गंगानगर जिले के सूरतगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा आदि क्षेत्रों में जल स्तर ऊँचा होने तथा पानी के ठहराव से 'सेम' की समस्या गम्भीर हो गई है।)।

-:17:-

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>सतत् विकास में जीवन विज्ञान और वानिकी की अहम भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>चर्चा में क्यों?</b> : वनस्पति विज्ञान, वानिकी व सामाजिक विकास के बीच अंतरसंबंधों पर वैज्ञानिक संवाद एवं शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मानसरोवर स्थित IIS (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई।</li><li>■ <b>विषय:</b> 'सेल्स टू कम्युनिटीज: इंटरलिंग्किंग लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री एंड सोशल डेवलपमेंट'।</li><li>■ <b>आयोजक:</b> वनस्पति शास्त्र विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।</li></ul>



## भूगोल एवं भू-विज्ञान

### उर्मिया झील

#### चर्चा में क्यों?

- ईरान में भीषण सूखे के बीच उर्मिया झील बेसिन में कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया।



#### मुख्य बिन्दु:

- **अवस्थिति:** उत्तर-पश्चिम ईरान के अजरबैजान क्षेत्र में।
- उच्च वाष्पीकरण के कारण लवणीय झील के रूप में स्थित।
- रामसर आर्द्रभूमि और यूनेस्को जैव मण्डल अभयारण्य के रूप में नामित यह झील 1990 के दशक से सिकुड़ रही है।

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### स्थानीय निकाय: 16वाँ वित्त आयोग

#### चर्चा में क्यों?

- 16वें वित्त आयोग ने अगले पाँच वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) के लिए भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को कुल लगभग ₹7.9 लाख करोड़ का अनुदान देने की सिफारिश की है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### स्थानीय निकाय वित्त-पोषण में चुनौतियाँ

- संरचनात्मक राजस्व अंतराल:** उदाहरण के लिए- संपत्ति कर का संग्रह बहुत कम है, क्योंकि संपत्ति के रिकॉर्ड अधूरे व गलत हैं, कवरेज कम है।
- केंद्र/राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता:** पंचायतों के राजस्व का 90% से अधिक हिस्सा सरकारी अनुदानों पर निर्भर है।

--:20:--

- **ऋण और पूँजी बाजार तक सीमित पहुँच:** भारत में नगरपालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला कर्ज GDP के 0.05% से भी कम अनुमानित है।
- **अन्य:** अविकसित बॉण्ड बाजार; डेटा अंतराल और लेखांकन संबंधी समस्याएँ; राज्य वित्त आयोगों (SFCs) के गठन में देरी आदि।

## 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- **संपत्ति डेटाबेस:** राज्यों को एक नागरिक-अनुकूल GIS-आधारित संपत्ति कर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** कुल अनुदान को ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए।
- **शहरीकरण प्रीमियम:** आसपास के गाँवों को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **संवैधानिक संशोधन:** संविधान के अनुच्छेद 280(3) (bb) और (c) की उस बाध्यता को हटाना चाहिए, जो केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर सिफारिशें करने के लिए बाध्य करती है।
- **सर्वोत्तम प्रथाएँ:** नीति आयोग द्वारा राज्य वित्त आयोगों के कामकाज का अध्ययन करने और राज्यों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह प्रकाशित करने की सिफारिश की गई है।

## स्थानीय निकायों के वित्त-पोषण स्रोत

- **स्वयं का कर राजस्व:** संविधान के अनुच्छेद 243X के तहत।
- **गैर-कर राजस्व:** इसमें लाइसेंस शुल्क, परमिट जारी करने का शुल्क आदि।
- **अंतर-सरकारी अंतरण:** वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अनुदान, राज्यों द्वारा अंतरण, और योजना-विशिष्ट अंतरण।
- **उधारियाँ:** म्युनिसिपल बॉण्ड्स, सामान्य दायित्व बॉण्ड
- **अन्य तरीके:** लघु शहरी निकायों के लिए पूलड फाइनेंसिंग (समूह के जरिए वित्त प्राप्त करना), भूमि मुद्रीकरण आदि।

## समाजशास्त्र

### भारत में बुजुर्गों की देखभाल: केंद्रीय बजट 2026-27

#### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय बजट 2026-27 में NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुरूप कार्यक्रमों के माध्यम से एक वर्ष में 1.5 लाख देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य भारत में बुजुर्गों की देखभाल (जेरियाट्रिक) संबंधी कार्यबल को मजबूत करना है।

#### मुख्य बिन्दु:

##### बुजुर्गों की देखभाल को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों?

- **बुजुर्गों की जनसंख्या:** वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में जनसंख्या का 10% से अधिक हैं और 2050 तक इनके 19.5% तक पहुँचने का अनुमान है।
- **स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव:** इस आयु वर्ग के लिए चिकित्सा व्यय सामान्य से दोगुने से भी अधिक है।
- **ग्रामीण संकेंद्रण:** जहाँ चिकित्सा अवसंरचना का अभाव होता है।
- **सामाजिक समर्थन का क्षरण:** पारंपरिक पारिवारिक सहयोग में कमी, कानूनी अधिकारों के प्रति कम जागरूकता और घरेलू दुर्व्यवहार जैसी समस्याएँ।
- **अपर्याप्त वित्तीय सुरक्षा:** वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्यता, वित्तीय निर्भरता, और कम बीमा कवरेज।

##### बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित सरकारी पहलें

- **नीतिगत और कानूनी फ्रेमवर्क:** माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 लागू किया गया है; राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (NPOP) बनाई गई है।
- **स्वास्थ्य संबंधी पहलें:** बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है तथा आयुष्मान भारत, वयो मित्र आदि योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
- **सामाजिक और आर्थिक सहायता:** अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एल्डर लाइन (14567), सेज (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन- SAGE) पहल, सेक्रेड (सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल- SACRED) पोर्टल आदि।



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### FORGE पहल



#### चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम अति-महत्वपूर्ण खनिज मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान “फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट (FORGE)” शुरू करने की घोषणा की है।



#### मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** वाशिंगटन डीसी, अमेरिका।
- इसमें भारत सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया।
- **गठन:** FORGE का गठन खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है।
- MSP का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना था।

#### FORGE उद्देश्य:

- FORGE के साझेदार देश नीतिगत स्तर और परियोजना स्तर पर मिलकर काम करेंगे।
- इसका उद्देश्य विविध, लचीली और सुरक्षित अति-महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाएँगे।

## अभ्यास खंजर

### चर्चा में क्यों?

- संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वाँ संस्करण असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में शुरू हुआ।



### मुख्य बिन्दु:

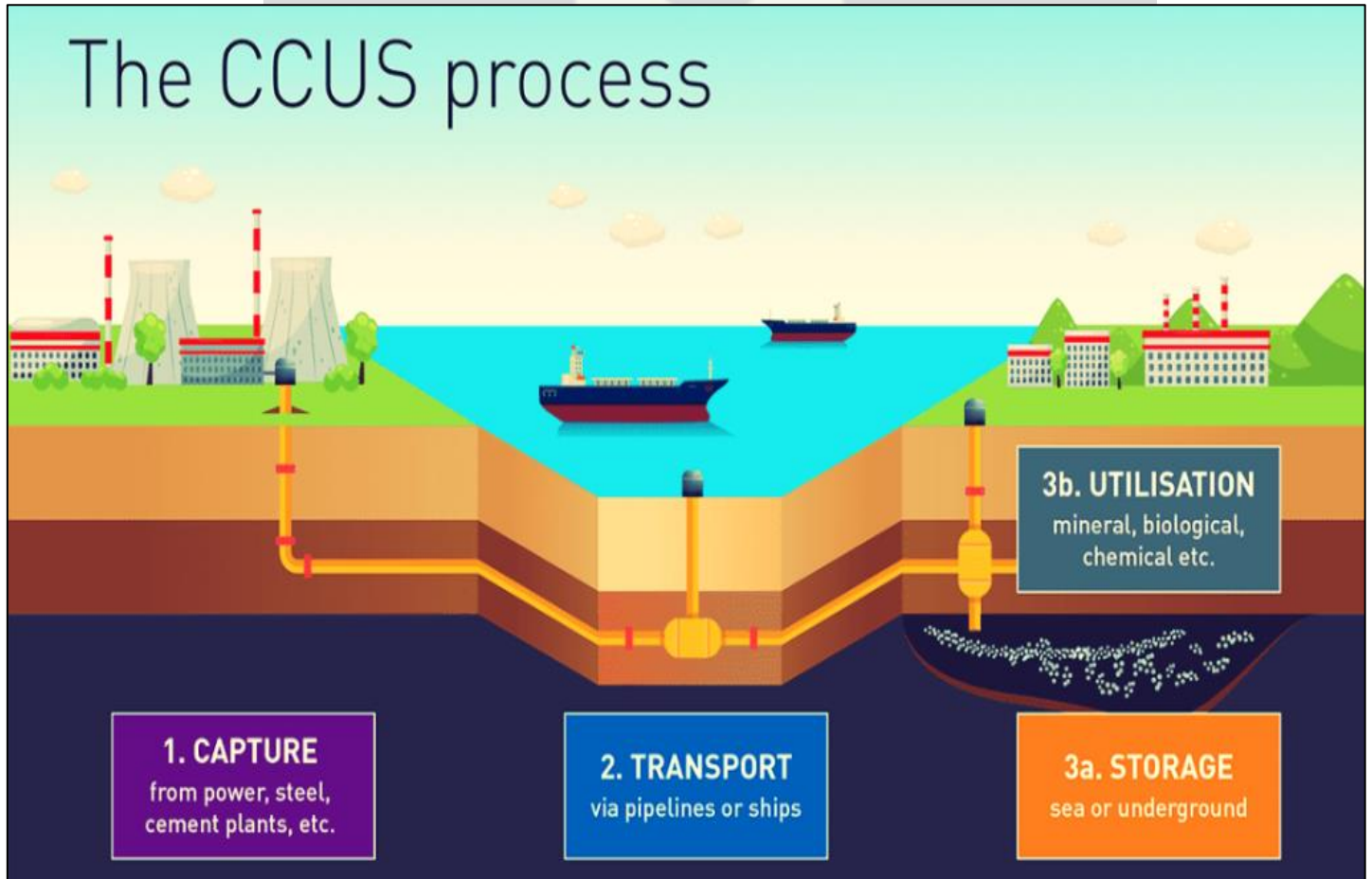
- **आयोजन:** यह भारत और किर्गिस्तान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
- **उद्देश्य:** दोनों देशों के बलों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाना।
- आतंकवाद-रोधी परिदृश्य पर ध्यान केन्द्रित करना।

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS): केंद्रीय बजट 2026-27

#### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया।



#### मुख्य बिन्दु:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के CCUS रोडमैप 2025 के अनुरूप इन प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।

## कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS)

- **CCUS क्या है:** इसमें विद्युत उत्पादन या औद्योगिक संयंत्रों जैसे बड़े कार्बन उत्सर्जक स्रोतों से CO<sub>2</sub> को कैप्चर किया जाता है, जहाँ ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन या बायोमास का उपयोग होता है।
- यदि कैप्चर की गई CO<sub>2</sub> का उपयोग साइट पर नहीं किया जाता है, तो इसे संपीड़ित कर परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है या इसे गहरी भूगर्भीय संरचनाओं में इंजेक्ट कर दिया जाता है।
- **प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ:** रासायनिक विलायक-आधारित अवशोषण, क्रायोजेनिक पृथक्करण, डायरेक्ट एयर कैप्चर, एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, बायो-एनर्जी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज आदि।

## इसकी आवश्यकता क्यों है?

- **उत्सर्जन कम करना:** सीमेंट, इस्पात या रसायन जैसे भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना।
- **कम लागत वाला हाइड्रोजन:** यह वहनीय कम कार्बन युक्त हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम बनाती है।
- **वैश्विक लक्ष्य:** 2050 तक वैश्विक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष कम-से-कम 1 बिलियन टन CCUS क्षमता की आवश्यकता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **प्रतिस्पर्धा:** कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे कार्बन-संबंधित प्रशुल्क के मद्देनजर उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना।

## चुनौतियाँ

- अपर्याप्त तकनीकी परिपक्वता
- संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक लागत
- प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और विस्तार की सीमित सुविधा
- अपर्याप्त वित्त-पोषण